(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item published in Daily "Tribune" dated 6 July, 1984 under the caption "Pak magnifying Jammu and Kashmir situation" stating that Pak media have started magnifying the political developmeats in Jammu and Kashmir; and

(b) if so, the steps taken to counteract Pakistani propaganda ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) Yes, Sir.

(b) Pakistan media coverage of recent internal Indian developments, including those in the State of Jammu & Kashmir was distorted and objectionable.

The question of distorted coverage by the Pakistan media, including official media, of internal developments in India has been taken up with the Pakistan Government on several occasions at different levels.

All possible efforts are made by our missions in Pakistan and elsewhere to correct such distortions.

U.S. Stand with Regard to Military Aid to Pakistan

2493, SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government has taken note of the fact that the U.S. Senate Foreign Relations Committee had adopted an amendment banning U.S. aid to Pakistan unless the U.S. President certified that it did not have or was not working on a nuclear bomb and preparation of nuclear bomb by Pakistan and also to President Zia's statement assailing the US moves to link military aid to Pakistan with its unclear programme as 'interference' in its domestic affairs; and

(b) if so, Government's information about the latest view of U.S. Government's stand with regard to military aid to Pakistan in the context of the latter's nuclear programme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b) Government are aware that on the 28th March, 1984 the U.S. Senate Foreign Relations Committee adopted an amendment banning aid to Pakistan, unless the U S. President certified that Pakistan was not pursuing a nuclear weapons programme and did not possess nuclear weapons. Subsequently, on the 3rd April, 1984, the same committee reversed itself. However, Government understand that the subject of Pakistan's nuclear programme is likely to be discussed once again by the Senate Foreign Relations Committee in the context of the Foreign Aid Bill.

No change in the U.S. Government's decision to provide military aid to Pakistan has come to Government's attention.

8 अगस्त, 1984 को होने वाली सदन की बैठक के लिए परमाणु ऊर्जा के बारे में भारत लीबिया वाणिज्यिक सौदा

2494. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :**

श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों में परमाणु ऊर्जा के सम्बन्ध में लीबिया के साथ एक वाणिज्यिक सौदा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सबन्ध में तथ्य क्या हैं और यह सौदा करने वाले लोगों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस सौदे में कोई अनियमितता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सबन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)

(क) और (ख) परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिमय प्रयोजनों के लिए करने के एक समझौते के ज्ञापन पर सन् 1978 के जुलाई मास में प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई तथा समाजवादी जन लीबियाई अरब जम्हारिया के स्टाफ मेजर जालौद ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए थे। तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीस भी बातचीत में शामिल थे।

(ग) और (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसे करार के निष्पादन में शामिल नहीं किया गया था, करार के कुछ प्रावधानों से पूर्णतया सहमत नहीं था। वैज्ञानिकों के आरम्भिक आदान-प्रदान के अतिरिक्त और कोई कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन का कालातीत हो चुका है।

ताँबे के आयात पर शुल्क में रियायत

2495. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तांबे के निर्यात पर शुल्क में रियायत देने की घोषणा की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने इस रियायत का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में में कुछ कदम उठाये हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) माननीय सदस्य का आशय संभवत हिन्दुस्तान-कापर लिमिटेड के तांबा रिवर्टो का विदेश में प्रद्रावण हेतु निर्यात और बाद में उसके आयात से है। चूंकि इसमें हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा स्वयं उत्पादित माध्यमिक तांबा धातु के निर्यात और बाद में उसके आयात की बात थी, इसलिए ऐसे आयातों पर लागू पूर्ण सममूल्य शुल्क की अदायगी पर, वापस प्राप्त तांबा वायर बार और वायर रौडवपर मूल और पूरक सीमा शुल्क से छूट देने का तदर्थ आदेश जारी किया गया है। टोल प्रद्रावण के बाद प्राप्त तांबा धातु हिन्दुस्तान-कापर लिमिटेड द्वारा मात्र उन प्रवर्तित मूल्यों पर बेची जा रही हैं जो खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित ऐसे माल के लिए मूल्य निर्धारण समिति द्वारा तय किये जाते हैं। ये मूल्य हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा टोल प्रद्रावित तांबे पर हुए व्यय से कम होते हैं। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए छूट का लाभ उपभोक्ताओं को सुलभ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान की सैन्ट्रल इन्टैलीजेंस एजेंसी द्वारा भारतीयों का रोका जाना

2496. **श्री निहाल सिंह :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठ भारतीय यात्रियों जिन्हें सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पहले ही जाने की अनुमति दे दी गई थी, को पाकिस्तान की सैन्ट्रल इन्टैलीजेन्स एजेंसी द्वारा देश के सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन करते हुए रोक लिया गया और एक विमान द्वारा कहीं और ले जाया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से पूछताछ की है; और